सूचना
यदी आप को नियमित दैनिक सुफ्फा का अंक प्राप्त नही हो रहा है या फिर आप दैनिक सुफ्फा हासिल करना चाहते है तो इस नम्बर पर संपर्क करे- 7620469536
औरंगज़ेब हुसैन (कार्यकारी संपादक)

दैनिक सुफ्फा
आम आदमी की आवाज़...
मुख्य संपादकः सज्जाद हुसैन अल्ताफ हुसैन
R.N.I. MAHHIN/2017/70719

Email:suffaakl@gmail.com ■ साल ८ वा ■ अंक ३१६ ■ तारीख, शनिवार २१ दिसंबर २०२४ ■ अकोला ■ पृष्ठ ४ ■ मूल्य ३ रूपये

जयपुर में LPG टैंकर में ब्लास्ट, अब तक ११ जिंदा जले; ४० गाड़ियां भी हुईं जलकर खाक

जयपुर-
जयपुर से अजमेर जाने वाले हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक आम दिन था. ट्रैफिक कम था क्योंकि सुबह के करीब ६ बज रहे थे. सर्द सुबह के बावजूद अचानक करीब एक किलोमीटर का इलाका आग से भभक उठा. कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही आग ने कई गाड़ियों और सड़क के किनारे बनी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते चारों ओर चीख-पुकार मच गई. लोग जब तक समझ पाते कि हुआ क्या है तब तक पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो चुका था. कारों में बैठे लोग सेकंड्स में झुलस गए थे. धीरे-धीरे आग की गिरफ्त में हाईवे पर जा रही गाड़ियां आ गईं. आग कैसे लगी सभी इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक दूसरे की जान बचाने में जुट गए थे. जैसे-तैसे पुलिस प्रशासन को खबर लगी और ताबड़तोड़ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ. इस दर्दनाक हादसे में अभी तक ११ लोगों की मौत हो चुकी है.दरअसल जयपुर-अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एक एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था. इस दौरान टैंकर ने यू टर्न लिया. कुछ गाड़ियों के ब्रेक लगे. सभी भारी-भरकर टैंकर के टर्न लेने का इंतजार कर रहे थे. बस इसी बीच जयपुर की तरफ से एक लोडेड ट्रक आया और टैंकर में टक्कर मार दी. ट्रक की टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर से गैस का रिसाव हो गया. लिक्विड फोर्म में गैस के रिसाव के बाद उसमें आग लग गई. गैस के तेजी से फैलने के साथ-साथ आग भी उतनी ही तेजी से फैली और आस-पास के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. जयपुर-अजमेर हाईवे पर हालात बद से बदतर तब हो गए जब एक-एक करके कुछ ही सेकंड्स में आग की लपटों ने ४० कारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया. शुरुआत में आग २०० मीटर के इलाके में फैली थी लेकिन बाद में यह करीब १ किलोमीटर के इलाके तक फैल गई. गाड़ियों में बैठे लोग गाड़ी के दरवाजे **(शेष पृष्ठ ३ पर)**

संसद के शीतकालीन सत्र का समापन: हंगामे के बीच दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली-
संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन, शुक्रवार (२० दिसंबर) को दोनों सदनों को शुरू होने के तुरंत बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. यह निर्णय भाजपा और कांग्रेस सांसदों के बीच डॉ. भीम राव आंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद और हंगामे के कारण लिया गया. भारी हंगामे के बीच लोकसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी) को भेजा. इससे पहले संसद में गुरुवार (१९ दिसंबर) को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के गेट पर किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. स्पीकर के मुताबिक़, यह निर्णय संसद की गरिमा बनाए रखने और इसकी कार्यवाही में व्यवधान रोकने के उद्देश्य से लिया गया. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, स्पीकर के कार्यालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी राजनीतिक दल, सांसद या सांसदों के समूह को संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी.गुरुवार को संसद परिसर में विपक्षी और एनडीए सांसदों के बीच डॉ. आंबेडकर को लेकर विवाद बढ़ गया था. आरोप हैं **(शेष पृष्ठ ३ पर)**

सुप्रीम कोर्ट का यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार

नई दिल्ली-
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (१८ दिसंबर) को गाजियाबाद में कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद के खिलाफ कार्रवाई करने में उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का आरोप लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व नौकरशाहों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के एक समूह द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि गाजियाबाद जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की है, जिसमें सभी सक्षम अधिकारियों को सांप्रदायिक गतिविधियों और नफरती भाषणों में लिप्त व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस पी.वी. संजय कुमार की पीठ ने कहा, 'अन्य मामले भी समान रूप **(शेष पृष्ठ ३ पर)**

परभणी हिंसा और सरपंच हत्याकांड मामले में होगी न्यायिक जांच, सीएम फडणवीस बोले- राजनीतिक परवाह किए बिना किया जाएगा दंडित

मुंबई-
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि परभणी हिंसा और बीड जिले में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री ने परभणी मामले में गिरफ्तारी के बाद हिरासत में मारे गए सोमनाथ सूर्यवंशी और सरपंच संतोष देशमुख के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है. उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि अराजकता फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को राजनीतिक जुड़ाव की परवाह किए बिना दंडित किया जाएगा.फडणवीस ने कहा कि महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल पहले ही मसाजोग गांव के सरपंच देशमुख की हत्या के मामले की जांच कर रहा है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा ३ से ६ महीने की समयसीमा के साथ एक न्यायिक जांच **(शेष पृष्ठ ३ पर)**

भारत में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा अभी भी उच्च स्तर पर, यूसीएफ ने राष्ट्रीय स्तर पर जांच की मांग

नई दिल्ली-
भारत में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं उच्च बनी हुई हैं, नवंबर २०२४ के अंत तक यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) हेल्पलाइन पर ७४५ घटनाएं दर्ज की गईं। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) एक दिल्ली स्थित नागरिक समाज संगठन है जो ईसाई मुद्दों पर केंद्रित है। इस डेटा में मणिपुर क्षेत्र में मानव और चर्च पर हुए हमलों को शामिल नहीं किया गया है। यूसीएफ की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, 'पिछले साल भी, मणिपुर में हुई दुखद हिंसा और रक्तपात के साथ-साथ २०० से अधिक चर्चों को ध्वस्त किए जाने को यूसीएफ के आंकड़ों में नहीं जोड़ा गया था।' यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम (यूसीएफ) द्वारा शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में ईसाइयों के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार के भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण की आलोचना की गई। इसमें बताया गया कि जब बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला हुआ, तो भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए सचिव स्तर के एक विशेष दूत को तुरंत भेजा। उन्होंने मांग की कि मोदी सरकार भारत में ईसाई अल्पसंख्यकों **(शेष पृष्ठ ३ पर)**

आरोपी सांसद पर बुलडोजर की कार्रवाई, बिजली चोरी के आरोप में घर की सीढ़ियां

मुंबई-
संभल दंगा के आरोपी सांसद जिया उर रहमान पर बिजली विभाग द्वारा १.९१ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीप सारी क्षेत्र में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान आज (२० दिसंबर) उनके आवास तक जाने वाली सीढ़ियां तोड़ दी गईं। संभल के सांसद के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई ऑनलाइन वायरल हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह तोड़फोड़ जिले में सार्वजनिक नालों से अतिक्रमण हटाने के लिए १५ दिनों के बड़े अभियान का हिस्सा थी। जिया उर रहमान के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई तब हुई जब उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग ने उन पर बिजली चोरी के आरोप में १.९१ करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया। कार्रवाई के तहत बिजली विभाग ने उनके आवास की बिजली भी काट दी, क्योंकि निरीक्षण में अवैध बिजली खपत के सबूत मिले थे।संभल के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया, 'संभल में आज भी बिजली निरीक्षण अभियान चल रहा है। विद्युत विभाग ने सांसद पर १.९१ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है और उनके आवास की बिजली आपूर्ति काट दी गई है।'

संभल में ५ तीर्थों और १९ कूपों का एएसआई ने किया सर्वेक्षण, नए मिले मंदिर का भी हुआ सर्वे

संभल-
संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने ५ महत्वपूर्ण तीर्थों और १९ कुओं का शुक्रवार को सर्वेक्षण किया है। जुमे के दिन शांतिपूर्ण तरीके से इस सर्वे को अंजाम दिया गया। इस दौरान मीडिया को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। इसके लिए एएसआई ने विशेष तौर पर प्रशासन से अपील की थी कि इसे मीडिया कवरेज से दूर रखा जाए। संभल में इस दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ से बचने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। जानकारी के मुताबिक, संभल में सर्वे का काम सुबह ६ बजे शुरू हुआ। इसमें प्रमुख तीर्थ स्थलों जैसे कि भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणि और प्राचीन तीर्थ श्मशान मंदिर शामिल थे। १९ कुंओं का भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने निरीक्षण किया है। ये सभी स्थान पुरातात्विक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सर्वेक्षण के बाद इन्हें संरक्षित करने की दिशा में फैसले लिए जा सकते हैं।संभल के जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि एएसआई की टीम ने शुक्रवार की सुबह सर्वे किया है। यह साढ़े ३ बजे दोपहर को कंप्लीट हुआ है। इसमें कुछ तीर्थों, कूपों का सर्वेक्षण किया गया है। जो अभी नया मंदिर मिला है, उसका भी सर्वे किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि एएसआई की टीम के पहुंचने से पहले ही हमने पैमाइश कर ली थी। तकरीबन ८ से १० घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। पैंसिया ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखा था। सर्वे कर टीम अपनी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो १४ दिसंबर को संभल एसडीएम वंदना मिश्रा ने पुरातत्व निदेशालय के निदेशक को पत्र लिखा था। जिसमें आग्रह किया गया था कि संभल में प्राचीन तीर्थों और कूपों के काल निर्धारण के लिए सर्वे किया जाए।

आंबेडकर की गरिमा को ठेस पहुंची, अमित शाह को 'ये शब्द' वापस लेने चाहिए: मायावती

नई दिल्ली-
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्यसभा में अपनी टिप्पणी से संविधान निर्माता बीआर आंबेडकर की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. उन्होंने भाजपा नेता से अपने शब्द वापस लेने को कहा.हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि शाह को पश्चाताप करना चाहिए क्योंकि पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है.मायावती ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा डॉ भीमराव आंबेडकर के बारे में संसद में अमित शाह द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों ने बाबा साहब की गरिमा और अस्तित्व को बहुत ठेस पहुंचाई है और एक तरह से उनका अपमान किया है. अब पूरे देश में उनके अनुयायियों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है और उन्हें अपने ये शब्द वापस लेने चाहिए और इसके लिए पश्चाताप भी करना चाहिए. अन्यथा, उनके (बीआर आंबेडकर) अनुयायी इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे वे **(शेष पृष्ठ ३ पर)**

शाहीन बाग से लेकर राहुल गांधी पर हमला: अराजक हिंसा को भड़काती भाजपा

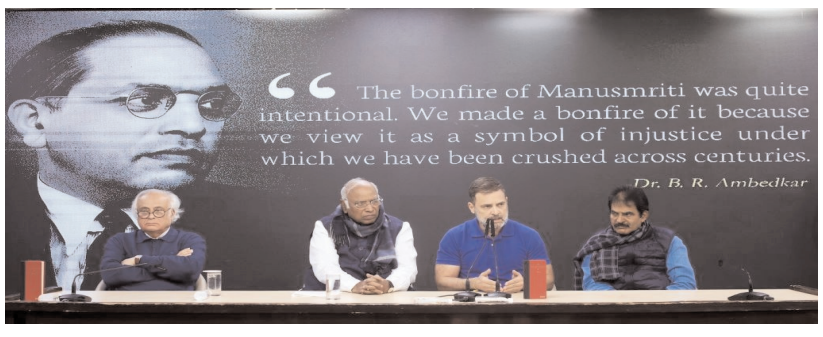

नई दिल्ली-
भारतीय जनता पार्टी देश को एक हिंसक अराजकता में धकेल रही है. १९ दिसंबर को संसद में उसके सांसदों ने योजनाबद्ध तरीक़े से हिंसक दृश्य पैदा किए और राहुल गांधी को घेरने की साज़िश की. राहुल गांधी पर उसने सबसे घृणित आरोप लगाया कि वे उसकी एक महिला सांसद की मर्यादा भंग करना चाहते थे. उन पर एफआई आर दर्ज की गई है. उसमें अनुसूचित जाति-जनजाति उत्पीड़न विरोधी क़ानून की धारा भी लगाई गई है. और तो और उन पर हत्या के प्रयास का आरोप भी है.यह इत्तेफ़ाक़ नहीं है कि भाजपा की जिस सांसद ने यह इल्ज़ाम लगाया है, वे नगालैंड की हैं. राहुल गांधी पर पर हत्या के प्रयास का आरोप भी लगाया गया है. इस आरोप को प्रामाणिक बनाने के लिए भाजपा के दो सांसदों को आईसीयू में दाखिल कराना पड़ा. माथे पर लगी छोटी पट्टी धीरे-धीरे तक़रीबन पगड़ी में बदल गई. हस्पताल के प्रमुख अधिकारी को बयान देना पड़ा कि वे निगरानी में हैं और उनकी हालत स्थिर करने की कोशिश की जा रही है. यह इतना हास्यास्पद है लेकिन उतना ही भयानक भी अगर हम इसके पीछे की साज़िश को समझ पाएं. राहुल गांधी पर यह हमला बहुत ही योजनाबद्ध है. चूंकि पिछले कुछ वक्त से राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर ज़ोर दे रहे हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न के गंभीर आरोप के हथियार से मारने की कोशिश की जा रही है. उसी प्रकार उत्तरपूर्व के एक राज्य मणिपुर में हिंसा पर लगातार ध्यान दिलाने और सरकार को जवाबदेह बनाने की उनकी और विपक्ष की कोशिश का जवाब है उत्तरपूर्व के ही एक दूसरे राज्य नगालैंड की एक महिला द्वारा उन पर मर्यादा भंग करने का आरोप. यह सब कुछ इतना पारदर्शी है लेकिन

भाजपा को यक़ीन है कि उसका सबसे बड़ा समर्थक और प्रचारक भारत का बड़ा मीडिया इस साज़िश में उसके साथ रहेगा और इस घटिया झूठ को सच में बदल देगा. बहुत सारे विश्लेषक इसमें तटस्थ रुख अपनाकर कहते रहेंगे कि अगर आरोप है तो कुछ न कुछ तो हुआ होगा. राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से सफ़ाई मांगी जाती रहेगी.एक रोज़ पहले तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के दूसरे पदाधिकारी बाबा साहब आंबेडकर पर संसद में की गई उनकी अहंकारपूर्ण टिप्पणी की सफ़ाई दे रहे थे. यह अस्वाभाविक नहीं था कि विपक्ष उसे मुद्दा बनाए. इसके बाद भाजपा रक्षात्मक होने को मजबूर थी. लेकिन अपने स्वभाव के मुताबिक़ उसने विपक्ष के विरोध का जवाब आक्रामकता के साथ देने का फ़ैसला किया.किसी भी विरोध को नष्ट कर देने का सबसे कारगर तरीक़ा है हिंसा. भाजपा ने पिछले १० साल में हर विरोध का जवाब हिंसा से दिया है. भीमा कोरेगांव में दलितों की सभा में भाग लेने वालों पर हिंसा की गई. फिर इस हिंसा के लिए सरकार के आलोचकों को ही ज़िम्मेदार ठहराकर उन्हें जेल में डाल दिया गया. २०१८ में अप्रैल में दलितों ने भारत बंद का आह्वान किया था. उस दिन दलितों पर हिंसा की गई और सैकड़ों दलितों पर मुक़दमा दर्ज किया गया. नागरिकता के क़ानून के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ तो उस पर एक बार नहीं कई बार हिंसा की गई. शाहीन बाग धरना स्थलों पर सुनियोजित हमले किए गए. किसान आंदोलन के दौरान हमने कई बार .**(शेष पृष्ठ ३ पर)**

अग्रलेख

सहयोग संग सावधानी

भारत और चीन के बीच बुधवार को हुई विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत में बनी सहमति इस बात का ठोस संकेत है कि दोनों देशों के रिश्तों में पिछले चार साल से आया ठहराव धीरे-धीरे दूर हो रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और इससे जुड़े कई किंतु-परंतु कायम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर बैठक के दौरान हुई मुलाकात के बाद से मतभेद दूर करने की प्रक्रिया में जो तेजी आई, उसका असर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (थ्ंण्) पर बने माहौल पर भी दिखा। पांच साल के अंतराल पर हुई विशेष प्रतिनिधियों की बैठक में सहमतियों पर अमल की तो पुष्टि हुई ही, यह संकेत भी मिला कि अब दोनों पक्ष इससे आगे बढ़ने को तैयार हैं। बॉर्डर ट्रेड, ट्रांस बॉर्डर नदियों पर डेटा शेयरिंग और मानसरोवर यात्रा की संभावनाएं वाकई उत्साह बढ़ाने वाली हैं।जैसे-जैसे सीमा संबंधी मसलों पर सहमति बन रही है और वहां माहौल सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है, दोनों देशों के रुख में सहयोग पर जोर भी बढ़ता जा रहा है। ध्यान रहे, चीन का काफी समय से आग्रह रहा है कि थ्ंण् से जुड़े मसलों को एक तरफ करके सहयोग बढ़ाया जाए, लेकिन भारत अपने इस रुख पर अडिग रहा कि जब तक थ्ंण् पर हालात सामान्य नहीं होते, रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। ऐसे में यह गौर करने वाली बात है कि अब भारत की तरफ से भी सहयोग का दायरा बढ़ाने की संभावना पर पॉजिटिव रुख दर्शाया जा रहा है।इस बात को भी कुछ हलकों में रेखांकित किया गया है कि संबंधों में सुधार और बातचीत में प्रगति को व्यक्त करने के दोनों पक्षों के तरीकों में पूरी तरह समानता नहीं है। मिसाल के तौर पर, बातचीत के बाद दोनों तरफ से जो अलग-अलग बयान जारी किए गए, उनमें अंतर है। जहां चीन के बयान में स्पष्ट शब्दों में सर्वसम्मति के छह बिंदु गिनाए गए हैं, वहीं भारत के बयान में इन्हें सर्वसम्मति करार देने से बचा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की ओर से बुधवार को ही जारी पेंटागन की सालाना रिपोर्ट की यह बात भी गौर करने लायक है कि चीन ने न तो गलवान घाटी में जून २०२० को हुई सैन्य झड़प के बाद इस क्षेत्र में बढ़ाई गई सैन्य तैनाती में कोई कमी की है और न ही टैंकों, मिसाइलों व अन्य भारी हथियारों की संख्या में कोई कटौती की है। हालांकि अभी उस इलाके से सैन्य वापसी की प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है, लेकिन फिर भी चीन के पिछले रेकॉर्ड को देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता।

यह समाचार पत्र मालक, प्रकाशक **सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन**, इन्होने मुद्रक - औरंगज़ेब हुसेन सज्जाद हुसेन, मुद्रण स्थल- **हुसेनी प्रिटींग प्रेस,** हुसेनी कॉम्प्लेक्स, वाशिम बायपास, अकोला ता.जि. अकोला (महाराष्ट्र) यहा छापकर ऑफीस : **दैनिक सुफ्फा,** जनता भाजी बाज़ार, अकोला जि. अकोला यहां से प्रकाशित किया. **संपादक : सज्जाद हुसेन अलताफ हुसेन** प्रकाशित लेख और खबरों से संपादक सहमत है ऐसा नही. (पी.आर.बी.ॲक्ट के अनुसार संपादक उत्तरदायी होंगे) सभी प्रकरण अकोला न्यायालय के अंतर्गत रहेंगे.

रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान सहित आठ देशों तक चीन ने बनाई सुरंग

वाशिंगटन-
चीन ने दुनिया की सबसे लंबी मोटरवे टनल को बनाने के लिए पहाड़ों के नीचे खुदाई शुरू कर दी है. यह तीन अरब पाउंड के महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बनाई जा रही है. इस प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही ये टनल १३ मील लंबी है. टियनशान शेंग्ली टनल, दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक को पार करेगी. इसके जरिए लोगों के आने जाने के समय में थोड़ी बचत होगी.इस टनल को चीन के शिनजियांग प्रांत में बनाया जा रहा है, जो दुनिया की सबसे विविधताओं से भरी हुई और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थितियों में से एक है. इस टनल के निर्माण से यात्रा के समय को कम करने के साथ-साथ सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी सुधार होगा. मोटरवे टनल का निर्माण कार्य २०२५ के अक्टूबर में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा. इस टनल से टियनशान पर्वतों से गुजरने वाली यात्रा का समय लगभग २० मिनट में कम हो जाएगा.इससे दक्षिणी शिनजियांग के एक प्रमुख शहर उरुमकी से कोरला तक की ३०० मील की यात्रा भी दो घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाएगी. इस परियोजना पर निर्माण कार्य २०१६ में शुरू हुआ था और २०३१ में पूरा होने की उम्मीद है.विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पूरा होने से शिनजियांग के अविकसित हिस्से में व्यापार और आर्थिक विकास को निश्चित रूप से फायदा मिलेगा. मध्य एशिया एक उचित रिटर्न- रिस्क का मिश्रण प्रदान करता है. ये विशेष रूप से अपने समृद्ध ऊर्जा भंडार के लिए प्रसिद्ध है. आर्थिक लाभ के अलावा, सुरंग चीन को भू-राजनीति के मामले में भी काफी फायदा पहुंचाने वाली है. इस परियोजना के लिए शी जिनपिंग की सरकार ने ३ अरब पाउंड का निवेश किया है. यह परियोजना शिनजियांग के आर्थिक विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. शिनजियांग एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक क्षेत्र है, जिसकी सीमा आठ देशों से लगती है, जिनमें रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं.

यह क्षेत्र मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है. इसकी स्थिति के कारण ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य केंद्र बनाती है.

मोसाद ने कैसे की थी हिजबुल्लाह के पेजर ब्लास्ट की तैयारी, पहली बार इजरायली खुफिया एजेंट का कबूलनामा

तेल अवीवः
इजरायल ने चंद महीनों में दुनिया के सबसे शक्तिशाली आतंकवादी समूह कहे जाने वाले हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। हिजबुल्ला पश्चिम एशियाई देश लेबनान की सत्ता को नियंत्रित करता था। इसके पास करीब ५०००० सशस्त्र लड़ाकों की फौज थी, जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त था। इसके बावजूद इजरायल ने न सिर्फ हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को मार गिराया, बल्कि उनके हजारों लड़ाकों में से अधिकतर को हताहत कर दिया। इसकी शुरुआत उस पेजर विस्फोट से हुई, जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके किया करते थे। अब पहली बार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एक पूर्व एजेंट ने कैमरे के सामने स्वीकार किया है कि उन्होंने कैसे इसकी प्लानिंग की थी।मोसाद के एजेंट ने इस धमाकेदार डॉक्यूमेंट्री में इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने इस तरह के हमलों के लिए कैसे दशकों तक एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाए थे। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम ण्ँए ६० श्ग्हलू है, जिसे लेस्ली स्टाहल ने होस्ट किया है। इस शो में भाग लेने वाले इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के रिटायर्ड एजेंटों ने कम्युनिकेशन हैक को स्टेप-बॉय-स्टेप विस्तार से बताया है। इंटरव्यू में अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए दोनों पूर्व मोसाद एजेंटों ने फेस मास्क और चश्में पहन रखे थे। इंटरव्यू में उनकी आवाज भी बदल दी गई है। इस इंटरव्यू में इजरायली मोसाद एजेंट सितंबर में हिजबुल्लाह के खिलाफ खुफिया अभियानों के बारे में बात करते दिखाई दिए। मोसाद एजेंटों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सैकड़ों पेजर और वॉकी टॉकी में एक साथ ब्लास्ट किया। इस रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस विस्फोट में कम से कम ३७ लोग मारे गए और ३००० से अधिक घायल हो गए। इस हमले ने ईरान और उसके सहयोगियों को यह संदेश दिया कि इजरायल एक ही पल में सैकड़ों लोगों पर हमला कर सकता है। इन विस्फोटों का असर इतना बड़ा था कि सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, बल्कि ईरान ने भी वॉकी टॉकी और पेजर से इस्तेमाल को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था।

सीरिया में अमेरिका ने दोगुनी की सैनिकों की संख्या, अबू जुलानी से मिलने जाएगा डेलीगेशन, क्या तुर्की के हमले का सता रहा डर?

दमिश्कः
बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद उथल-पुथल से गुजर रहे सीरिया में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सीरिया में अल कायदा और आईएसएस जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े रहे अबू जुलानी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार से बातचीत के लिए भी अमेरिका उत्सुक दिख रहा है। अमेरिका जल्दी ही सीरिया में अपना डेलीगेशन भेजने पर विचार कर रहा है। अमेरिका की ये चिंता इसलिए है क्योंकि सीरिया में उथल पुथल का फायदा उठाने में कई देश लगे हैं। इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्गोदन का भी नाम है, जो सीरिया के मुद्दे पर एक्टिव हैं। इजरायल भी सीरिया में जमीन पर कब्जा कर रहा है। वहीं अमेरिका ये भी चाहता है कि फिर से ईरान की स्थिति सीरिया में मजबूत हो। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ब्लूमबर्ग सर्विलांस प्रोग्राम में बताया कि बाइडन प्रशासन सीरिया में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। ब्लिंकन ने पहले ही पुष्टि की थी कि अमेरिका ने प्ऊए से संपर्क किया है। अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा कर दी है। सैनिकों की संख्या ९०० से बढ़ाकर २,००० कर दी गई हैं। इसे कहीं ना कहीं ये डर भी है कि तुर्की अपने बॉर्डर के आसपास के सीरियाई हिस्सों पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। ऐसे में प्ऊए से बात करते हुए वह ऐसी स्थिति को रोकना चाहता है। सीरिया में जिस प्ऊए से अमेरिका बात करने के संकेत दे रहा है, उसे वह आतंकवादी संगठन मानता है। अमेरिका ने प्ऊए के नेता अबू मोहम्मद जुलानी पर १० मिलियन डॉलर का इनाम है। हालांकि पिछले हफ्ते जारी एक बयान में अमेरिका कह चुका है कि अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो वह सीरिया की नई सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार है। इन शर्तों में गैर-सांप्रदायिक नेतृत्व का गठन, अल्पसंख्यकों- महिलाओं का सम्मान और रासायनिक हथियारों का खात्मा शामिल है।अल जुलानी ने भी अमेरिका से करीबी के संकेत दिए हैं। यूके के अखबार द टाइम्स से जुलानी ने कहा है कि इजरायल के लिए सीरिया खतरा नहीं बनेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि जुलानी की ये अमेरिका से मान्यता हासिल करने की कोशिश है। जुलानी को पता है कि इजरायल पर हमलावर होने का मतलब पश्चिम और अमेरिका के साथ उलझना है। ऐसे में वह इजरायल से बनाकर चलते दिख रहे हैं।सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के एक वरिष्ठ फेलो विल टोडमैन ने एमईई से बात करते हुए कहा कि सीरिया में हो हुआ है, वह अप्रत्याशित था। ऐसे में अब निश्चित रूप से इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं कि सीरिया में नई सरकार किस दिशा में जाएगी। इस पर भी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी, हमें अभी दमिश्क की ओर देखना होगा।

गाजा, सीरिया और अम्मान में फिलिस्तीनी... टूट जाएगी इजरायल और दोस्त जॉर्डन के बीच ३० साल पुरानी शांति की डोर, बढ़ी चिंता

तेल अवीवः
सीरिया की अस्थिरता ने इजरायल और जॉर्डन के बीच की शांति को भी खतरे में डाल दिया है, जो दोनों क्षेत्र के अहम सहयोगी हैं। जॉर्डन ने इस साल ईरान के मिसाइल हमले से बचने में भी इजरायल की मदद की थी। दोनों पड़ोसियों ने क्षेत्रीय तनाव और अलग-अलग राजनीतिक हितों के बीच शांति बनाए रखने की विशेषता दिखाई है। इजरायल और जॉर्डन के बीच नाजुक शांति के तीस साल बाद सीरिया में अस्थिरता ने कई बड़ी चिंताएं पैदा की हैं। गाजा में युद्ध के बाद अब सीरिया की स्थिति जॉर्डन के लिए मुश्किल का सबब बन रही है, जो इजरायल के लिए भी फ्रिक की वजह है।इजरायली वेबासइट वायनेट से बातचीत में इजरायल-जॉर्डन संबंधों के विशेषज्ञ रॉन शेट्‌जबर्ग कहते हैं कि जॉर्डन की सरकार चरमपंथी तत्वों को बाहर निकलने के लिए निश्चित खुलापन दिखाती है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त गुप्त खुफिया प्रयासों को लागू करती रही है लेकिन अब कुछ चिंताए हैं। सीरिया में बशर असद शासन के पतन के प्रभाव जॉर्डन तक भी पहुंच सकते हैं, जहां कट्टरपंथी गुटों ने सत्ता पर कब्जा किया है। सीरिया का प्रभाव जॉर्डन में दिखा तो इसका इजरायल पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इजरायल और जॉर्डन ४८० किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये इजराइल की सबसे लंबी सीमा है। जॉर्डन की तकरीबन आधी आबादी फिलिस्तीनी मूल की है। ये इजरायल के साथ संबंध को एकदम पसंद नहीं करती है।

इजरायली जनसंख्या और आव्रजन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, हाल के वर्षों में जॉर्डन के साथ सीमा के माध्यम से अवैध घुसपैठ की संख्या में वृद्धि हुई है। तेल अवीव विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के शोधकर्ता डॉक्टर ओफिर विंटर का कहना है कि ईरान इजरायल के खिलाफ अपने 'प्रतिरोध के धुरी' में जॉर्डन को अखाड़ा बनाने के लिए देश के शासन को कमजोर कर रहा है।

जॉर्डन की सीरिया, सऊदी अरब और इराक के साथ भी सीमाएं हैं। इन सीमाओं पर भी इजरायल के लिए शत्रुता के तत्व मौजूद हैं। जॉर्डन के राजनीतिक विश्लेषक आमेर सबैलेह का कहना है कि इजरायल की अब तक की सबसे दक्षिणपंथी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद से चीजें बदली हैं। नेतन्याहू सरकार के उग्र राष्ट्रवादी नीतियों से भी अम्मान और यरूशलेम के बीच संबंध तेजी से तनावपूर्ण हुए हैं।

इजरायली सरकार का उग्र रवैया जॉर्डन शासन के लिए बचाव का रास्ता नहीं छोड़ रहा है। विटंर का कहना कि जॉर्डन की स्थिरता के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं है लेकिन कोई भी अस्थिरता इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा कर सकती है। सीमा पर किसी भी अस्थिरता की स्थिति में इजराइयल को सीमा की रक्षा के लिए अधिक सेना तैनात करने की आवश्यकता होगी। ये उसके लिए रक्षा और आर्थिक लिहाज से बोझ होगा। इजरायल पहले ही युद्ध में उलझा है तो उसकी आर्थिक स्थिति कठिन है। ऐसे में ये उसके लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा।

मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल में सांस्कृतिक और क्रीडा सप्ताह मनाया गया

नई दिल्ली-

अल हुदा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ता, मालेगाव जि, नाशिक द्वारा संचालित न्यू जोगड़ेकर प्लाट स्थित मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम और क्रीडा सप्ताह बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नात, किरत, स्पीच, क्विज इत्यादि कार्यक्रम रखे गए जिसमें स्कूल के सभी छात्र एवं छात्राओं ने भाग लेकर प्रथम और द्वितीय स्थान पाकर अपनी योग्यता और कौशल दिखाया। इसी तरह क्रीडा में छात्रों ने क्रिकेट, फुटबॉल, रिले, गोला फेक, और स्लो

साइकलिंग जैसे खेलों में भाग लिया। वहीं छात्राओं ने भी लेगोरी, डोजबॉल , नींबू चमचा, बकेट रेस, और म्यूजिकल चेयर में भाग लेकर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस तरह एक सप्ताह तक चलने वाला सांस्कृतिक और क्रीडा का समापन बड़े हर्षोल्लास के साथ समाप्त हुआ। इन खेलों और कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए स्कूल के मुख्यअध्यापक अहमद हसन साहब और सभी शिक्षक गण अब्दुल अज़ीज़ सर, शहजाद खान सर, सलीम अहमद अंसारी सर्, साजिद इकबाल सर, सैयद नदीम सर, आबिद हुसैन सर, आरिफ हुसैन सर, फहीम साजिद सर, सैयद साजिद सर, अजीम ज़नाब, नें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया

एमपीजे ने किया परभणी के संविधान अपमान एवं सूर्यवंशी मृत्य प्रकरण का निषेध, मुख्यमंत्री को भेजा निवेदन

नई दिल्ली-

अकोला-परभणी मे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के प्रतिमा के समीप हुये संविधान की प्रतिकृती को तोडफोड प्रकरण का मुव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टीस फॉर वेलफेअर अर्थात एमपीजे ने निषेध कर इस प्रकरण की कडी जाच कर दोषींयो पर कारवाई की मांग मुख्यमंत्री फडणवीस को जिलाधिकारी मार्फत भेजे निवेदन मे की.परभणी मे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर के पुतले के सामने संविधान के प्रतिकृती की तोडफोड की गयी.इस घटना मे पुलीस अत्याचार मे निर्दोष सोमनाथ सूर्यवंशी का मृत्यू हुवा.इस दुर्दैवी एवं झकझोर करनेवाली घटना की न्यायालयीन जाच कर इस घटना मे पुलीस अत्याचार मे मृत्यु हुये सूर्यवंशी को न्याय देकर इसमे दोषींयोपर कठोर कारवाई करने की मांग निवेदन मे की गयी.संविधान की सुरक्षा सर्वोपरी होकर उसकी रक्षा करना सभी का दायित्व है.

लिहाजा ऐसे गंभीर प्रकरण मे दोषीयो की जाच कर उनपर कठोर कारवाई करने की मांग निवेदन मे की गयी.इस निवेदन के समय एमपीजे के जिलाध्यक्ष मो.अतिकुर रहेमान, शहजाद अनवर, युवामुक्ती के मनोज भालेराव, रामधन शिरसाट, निकेश तायडे, अजय शिरसाट, संजय गवई, अ सत्तार, शे खातीम, झीनत सै. साबीर, आरेका जावेद, यास्मिम अ अतिक, नौशाद खान, व्ही बी तेलगोटे आदी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे.

जाहिर नोटीस

वि. ०२रे सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर), अकोला यांचे न्यायालयात

एम.जे.सी.नं. २१४५ / २०२४ प्रोसेस नं. : १८७८४ / २०२४
चौ. ता. : १४/०१ / २०२५ दिनांक : ०२/१२/२०२४

अर्जदार-
(१) नजेरा बी अब्दुल जहीर , पत्ता - रा. बिस्मिल्ला किराणा जवळ, इंदिरा नगर, अकोला ता. जि. अकोला
२) अब्दुल सलीम अब्दुल जहीर, रा. गरीब नवाज मसजीद जवळ, भारत नगर, अकोट फेल, अकोला ता. जि. अकोला
३) अब्दुल नाजिर अब्दुल जाहीर,
रा. भारत नगर, शिलोडा ता. जि. अकोला
४) अब्दुल जमीर अब्दुल जाहीर
रा. ताज चौक जवळ, इंदिरा नगर, अकोला ता. जि. अकोला
५) अब्दुल समीर अब्दुल जहीर
रा. अत्तरीय मसजीद जवळ, भारत नगर, अकोला ता. जि. अकोला
६) साजेदा परवीन अब्दुल जहीर, रा. मुगल प्लॉट मसजीद, वाशिम रोड, जुने शहर, अकोला ता.जि. अकोला
७) वहीदा बी सय्यद हुसैन
रा. अत्तरीय मसजीद जवळ, भारत नगर, अकोला ता. जि. अकोला

..... विरुध्द ....

गैरअर्जदार:- निल.
मयताचा पत्ता:- मयत:- अब्दुल जहीर अब्दुल हबीब
पत्ता:- रा. बिस्मील्ला किराणा जवळ, इंदिरा नगर, अकोट फाईल, अकोला, ता. व जि. अकोला.

या अर्थीउपरोक्त अर्जदार हयांनी मुंबई विनिमय अधिनियम १८२७, कलम २ अन्वये या न्यायालयात वारसा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्या अर्जामध्ये असे नमूद केले आहेकी, मयत अब्दुल जहीर अब्दुल हबीब यांचे दि.१६/०२/२०१९ रोजी अकोला येथे निधन झाले आहे.

वरील अर्जदार त्यांचे कायदेशिर वारस आहेत, त्याशिवाय इतर कोणीही मयतास वारस नाही. सबब वारस प्रमाणपत्र मिळण्यास अर्जदारांनी अर्ज दाखल केला आहे.

त्याअर्थी सदर अर्जामध्ये कोणाची कसल्याही प्रकारची हरकत असल्यास दिनांक १४/०१/२०२५ रोजी सकाळी ११:०० वाजता स्वतः जातीने अगर निर्दोष्ट केलेल्या वकीला मार्फत न्यायालयामध्ये हजर होउन आपली लेखी हरकत दाखल करावी. अन्यथा कोणाची कसल्याही प्रकारची हरकत नाही. असे गृहीत धरुन सदर अर्ज निकाली काढण्यात येईल. हयाची नोंद घ्यावी.

आज दिनांक ०२ / १२ / २०२४ रोजी माझे सही व न्यायालयाचे शिक्क्यानिशी दिले.

न्यायलयाचा शिक्का

आदेशानुसार,

अधिक्षक
दिवाणी न्यायालय (व. स्तर), अकोला

जाहिर नोटीस

वि. सह दिवाणी न्यायाधीश (क.स्तर), अकोला यांचे न्यायालयात

एम. जे. सी.नं. २१४४ / २०२४ प्रोसेस नं.: १८७८७ / २०२४
चौ. ता. १४/०१ / २०२५ दिनांक: ०२/१२/२०२४

अर्जदार:-
(१) संगीता शंकर यादव, पत्ता - रा. मोचीपुरा आकोट फैल, कल्याण केंद्र जवळ, अकोला ता. जि. अकोला

...विरुध्द.......

गैरअर्जदार:- निल.
मयताचा पत्ता:- मयतः- यशोदा मुन्ना यादव
पत्ता:- रा. मोचीपुरा, कल्याण केंद्र जवळ, अकोट फाईल, अकोला, ता. व जि. अकोला.

या अर्थीउपरोक्त अर्जदार हयांनी मुंबई विनिमय अधिनियम १८२७, कलम २ अन्वये या न्यायालयात वारसा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्या अर्जामध्ये असे नमूद केले आहे की, मयत यशोदा मुन्ना यादव यांचे दि.२४/११/२०२२ रोजी अकोला येथे निधन झाले आहे.

वरील अर्जदार त्यांचे कायदेशिर वारस आहेत, त्याशिवाय इतर कोणीही मयतास वारसनाही. सबब वारस प्रमाणपत्र मिळण्यास अर्जदारांनी अर्ज दाखल केला आहे.,

त्याअर्थी सदर अर्जामध्ये कोणाची कसल्याही प्रकारची प्रकारची हरकत असल्यास दिनांक १४/०१/२०२५ रोजी सकाळी ११:०० वाजता स्वतः जातीने अगर निर्दोष्ट केलेल्या वकीला मार्फत न्यायालयामध्ये हजर होउन आपली लेखी हरकत दाखल करावी.अन्यथा कोणाची कसल्याही प्रकारची हरकत नाही. असे गृहीत धरुन सदर अर्ज निकाली काढण्यात येईल. हयाची नोंद घ्यावी.

आज दिनांक ०२/१२/२०२४ रोजी माझे सही व न्यायालयाचे शिक्क्यानिशी दिले.

आदेशानुसार,

न्यायलयाचा शिक्का

अधिक्षक

दिवाणी न्यायालय (व.स्तर), अकोला

(पृष्ठ १ पर से..)

आंबेडकर की गरिमा को ठेस पहुंची, अमित शाह डॉ बीआर आंबेडकर के प्रति कांग्रेस के कुकृत्यों को नहीं भूल पाए हैं.'द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, मायावती ने कहा कि भारत के कमजोर वर्ग अपने वोट के लिए कांग्रेस और भाजपा की राजनीति देख रहे हैं, लेकिन अब उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता.मायावती ने कहा, 'पिछले दो दिनों से लोकसभा में दलितों और अन्य वंचित वर्गों के वोट के लिए सरकार और विपक्ष के बीच चल रही राजनीति, उनका 'मेरा आंबेडकर बनाम मेरा आंबेडकर' और सदन के बाहर उनकी धक्का-मुक्की अच्छी नहीं लगती.'मायावती ने कहा, 'देश में संविधान लागू होने के बाद से कांग्रेस नहीं बदली है. इसने आंबेडकर को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और उनके खिलाफ साजिश रची. यह अभी भी कमजोर वर्गों को संविधान के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित रखना चाहती है.'उन्होंने कहा, 'और मुझे नहीं लगता कि इस मामले में भाजपा कांग्रेस से पीछे रहेगी. वे भी इस समुदाय (अनुसूचित जाति) के मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीति करते रहते हैं. चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, वे वास्तव में आंबेडकर का सम्मान नहीं करते.'ज्ञात हो कि १७ दिसंबर को राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा था, 'अभी एक फैशन हो गया है ष्ठआंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर. इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता.'बुधवार को अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने बीआर आंबेडकर को भारत रत्न न देकर उनका अपमान किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार ने आखिरकार १९९० में उन्हें यह पुरस्कार दिया.

संसद के शीतकालीन सत्र का समापन: हंगामे के कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों को धक्का दिया, जिससे भाजपा सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों घायल सांसदों का हालचाल लिया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. उन पर धारा ११७, ११५, १२५, १३१, ३५१ और ३(५) के तहत केस दर्ज किया गया है.कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने एफआईआर के खिलाफ बयान दिया है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है, 'वे इतने हताश हो गए हैं कि राहुल जी पर झूठा इ्ं दर्ज करा रहे हैं. राहुल जी कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते हैं, यह बात मैं और पूरा देश जानता है, लेकिन ँव्झ राहुल जी पर आधारहीन इ्ं दर्ज करा रही है. देश के सामने ँव्झ की सच्चाई आ गई है, वे अडानी पर चर्चा नहीं चाहते, अंबेडकर जी का अपमान करते हैं. इसलिए अब वह देश का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं.'कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा है, 'संसद परिसर में मकर द्वार के सामने जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह एक सुनियोजित साजिश थी. १७ दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर अपमानजनक बातें कही थी और उससे ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया गया. जबकि गृह मंत्री के अपमानजनक बयान पर पूरे विपक्ष ने आपत्ति जताई थी. नेता प्रतिपक्ष श्री खरगे ने इ्श मोदी से मांग की थी कि गृह मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए. हमने मांग भी रखी थी कि अमित शाह माफी मांगें. अब इस घटनाक्रम में जो इ्ं दर्ज हुई है, वह राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि अंबेडकर जी और सामाजिक न्याय के खिलाफ है.'कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है, 'ँव्झ के सदस्य झूठा इ्ंकर रहे हैं. हमारी चुनौती है कि वे एक वीडियो भी दिखा दें जहां राहुल गांधी जी घायल सांसद के कहीं आसपास भी खड़े हों. आप देखिए किस तरह डंडे में झंडा लगाकर उन्हें लहराया जा रहा था, किस तरह मल्लिकार्जुन खरगे जी और राहुल गांधी जी के साथ धक्का-मुक्की की गई. महिला सांसदों को सदन के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया. उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई. लेकिन कुछ भी हो जाए, हमे लाठियां भी खानी पड़ जाए, तब भी हम अंबेडकर जी का अपमान नहीं होने देंगे.राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है, 'ँव्झ द्वारा राहुल गांधी जी पर किया गया इ्ंबेकार की बात है. अमित शाह ने जिस तरह से बाबा साहेब को अपमानित किया है, ँव्झ उस मुद्दे को डायवर्ट करने की कोशिश कर रही है. लेकिन देश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली, वो सच्चाई जानती है.'शिवसेना (उद्धव) के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है, 'ँव्झ द्वारा किया गया इ्ं ध्यान भटकाने का तरीका है. राहुल जी डरते नहीं हैं, न हम में से कोई डरता है. हमारी मांग यही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, क्योंकि उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया है.' कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है और सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद के प्रवेश द्वार पर रोकने और धमकाने की कोशिश की. राहुल ने गुरुवार को कहा था, 'मुझे अंदर जाने से रोका गया, धक्का दिया गया और धमकी दी गई. यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है. भाजपा संविधान पर हमला कर रही है और आंबेडकर जी की स्मृति का अपमान कर रही है.'राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर भाजपा सांसदों पर उन्हें शारीरिक रूप से धक्का देने का आरोप लगाया था. खरगे ने कहा था कि इस घटना में उनके घुटने चोटिल हो गए, और वे बमुश्किल सदन तक पहुंच सके. उन्होंने इसे हमला करार देते हुए इसकी जांच की मांग की था.वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों केसी वेणुगोपाल, माणिकम टैगोर और के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर भाजपा सांसदों के 'अलोकतांत्रिक आचरण' की शिकायत की था. उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के साथ धक्का–मुक्की उनके सांसद होने के अधिकारों का उल्लंघन है.कांग्रेस सांसदों ने अपने पत्र में लिखा, 'राहुल गांधी को शारीरिक रूप से रोका गया, जो न केवल उनके व्यक्तिगत सम्मान पर हमला है, बल्कि लोकतंत्र की भावना के भी खिलाफ है. भाजपा सांसदों का यह आचरण अस्वीकार्य है.'

सुप्रीम कोर्ट का यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित से गंभीर हैं. अगर हम इस पर विचार करेंगे तो हम पर बहुत दबाव पड़ेगा. आपको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए. हम इस पर विचार नहीं कर सकते.' याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि नरसिंहानंद को इस शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह नफरत फैलाने वाले भाषण में शामिल नहीं होंगे, जबकि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए.हालांकि, अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस कार्यक्रम की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि इसे वीडियो पर रिकॉर्ड किया जाए.अदालत ने कहा, 'अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (केएम) नटराज, कृपया अधिकारियों से कहें कि वे मामले पर नज़र रखें और वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जाए. सिर्फ़ इसलिए कि हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम इस मुद्दे से बच रहे हैं.'याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस संसद की वेबसाइट और विज्ञापनों में इस्लाम के अनुयायियों के खिलाफ कई सांप्रदायिक बयान शामिल हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले हैं.उत्तर भारत में कई जगहों पर पहले भी धर्म संसद के आयोजन खुलेआम सांप्रदायिक विषयों के कारण चर्चा में रहे हैं. मालूम हो कि कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद अपने बयानों को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं. सितंबर २०२२ में एक धार्मिक समारोह में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में पुलिस ने यति नरसिंहानंद, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे के खिलाफ केस दर्ज किया था. अलीगढ़ में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को बम से उड़ा देना चाहिए. नरसिंहानंद ने अलीगढ़ को उस स्थान के रूप में पारिभाषित किया था, जहां से 'भारत के विभाजन का बीज' बोया गया था.अप्रैल २०२२ में ही उन्होंने मथुरा में हिंदुओं से अधिक संतान पैदा करने की अपील की थी, ताकि भारत को आने वाले दशकों में 'हिन्दू विहीन' राष्ट्र बनने से रोका जा सके.इसी महीने में नरसिंहानंद के एक संगठन ने भारत को इस्लामिक देश बनने से बचाने के लिए हिंदुओं से अधिक बच्चों को जन्म देने का आह्वान किया था. संगठन ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में तीन दिवसीय धर्म संसद का आयोजन किया था. कार्यक्रम में नरसिंहानंद ने दावा किया था कि मुस्लिम योजनाबद्ध तरीके से कई बच्चों को जन्म देकर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं.इससे पहले उत्तर दिल्ली के बुराड़ी में ३ अप्रैल २०२२ को आयोजित 'हिंदू महापंचायत' कार्यक्रम में नरसिंहानंद ने फिर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का आह्वान करते पाए गए थे. इस संबंध में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. हरिद्वार धर्म संसद मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए नरसिंहानंद ने जमानत शर्तों का उल्लंघन करते हुए मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए ये नफरती भाषण दिए थे. इस मामले में नरसिंहानंद और अन्य वक्ताओं के खिलाफ दिल्ली के मुखर्जी नगर पुलिस थाने में नफरती भाषण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.यति नरसिंहानंद हरिद्वार धर्म संसद के आयोजकों में से एक थे. दिसंबर २०२१ में उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में आयोजित 'धर्म संसद' में मुसलमान एवं अल्पसंख्यकों के खिलाफ खुलकर नफरत भरे भाषण देने के साथ उनके नरसंहार का आह्वान भी किया गया था.धर्म संसद में यति नरसिंहानंद ने मुस्लिम समाज के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी करते हुए कहा था कि वह 'हिंदू प्रभाकरण' बनने वाले व्यक्ति को एक करोड़ रुपये देंगे.

शाहीन बाग से लेकर राहुल गांधी पर हमला: टिकरी और सिंघू सरहद पर धरने पर बैठे किसानों पर हमले देखे. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सरकार के आलोचकों पर हिंसक आक्रमण की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं.हिंसा के बाद हमेशा संदेह पैदा होता है. दो पक्ष बन जाते हैं. और जो पहले आरोप लगा देता है, उसका हाथ ऊपर रहता है दूसरे पक्ष को सफ़ाई देनी पड़ती है. भाजपा हर जन आंदोलन या विपक्ष के विरोध के दौरान हिंसा पैदा करके यही करती है. जिस विषय पर विरोध हो रहा था, वह चर्चा से ग़ायब हो जाता है, रह जाती है हिंसा. चूंकि सारा बड़ा मीडिया भाजपा समर्थक और विपक्ष का विरोधी है, वह पूरी बहस में हमेशा विपक्ष पर निशाना लगाता रहता है.अब तक यह सब कुछ सड़क पर होता था. भाजपा इस हिंसा को संसद तक ले गई है. संसद के भीतर गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार के कई नमूने भाजपा की तरफ़ से देखे गए हैं. १९ दिसंबर को यह शारीरिक हिंसा में बदल गया. हमने इसके पहले दूसरी सरकारों के दौरान सैकड़ों बार विपक्ष को विरोध प्रदर्शन करते देखा है. कभी सत्ता पक्ष ने विरोध का विरोध उस प्रकार नहीं किया. हमेशा ही सत्ता पक्ष अधिक संयम से काम लेता है. लेकिन भाजपा हमेशा इसके उलट काम करती आई है.१९ दिसंबर को भाजपा ने जो कुछ भी किया उसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है. वह राहुल गांधी की साख खत्म कर देना चाहती है. वह जिस जिस जगह कारगर हो सकते हैं, वह उनसे छीन लेना चाहती है. पिछली बार उनकी संसद सदस्यता समाप्त करने के पीछे यही वजह थी. इस बार भी तैयारी उसी की है. राहुल गांधी विपक्ष के एक मात्र ऐसे नेता हैं जिनका चेहरा पूरे भारत में लोग पहचानते हैं. उस चेहरे को ग़ायब करके ही विपक्ष को समाप्त किया जा सकता है.मीडिया इस दुष्प्रचार में शैतानी आनंद के साथ कूद पड़ा है. चुनौती कांग्रेस और विपक्ष के सामने है कि वह भाजपा की इस घिनौनी साज़िश से जनता को आगाह करे.

भारत में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा अभी भी उच्च पर अत्याचार की इन घटनाओं की जांच के लिए भारत सरकार के सचिव स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर की जांच स्थापित करने पर विचार करे।यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम की अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के २८ राज्यों में से २३ राज्यों में ईसाईयों को अलग-अलग स्तर की हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें सबसे अधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश (१८२) में हुईं, जबकि दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ (१३९) रहा। 'इसके अलावा, ईसाइयों के संवैधानिक अधिकारों को व्यवस्थित रूप से नकारा जा रहा है। खास तौर पर भारत की छोटी ईसाई आबादी को एंग्लो-इंडियन के आरक्षण के अधिकार से वंचित करके भारत में संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जा रहा है।' पीयूसीएल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार , स्थानीय पुलिस हिंसक अपराधियों के साथ मिलीभगत करती है और ईसाइयों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर आंखें मूंद लेती है।वे इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि पिछले पांच वर्षों से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग में कोई भी ईसाई सदस्य नहीं है। इसी तरह, राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी ईसाई सदस्यों को नहीं भर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लंबित है जिसमें भारत में ईसाई विरोधी हिंसा में शामिल निगरानी समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन २०२२ में प्रारंभिक सुनवाई के बावजूद, याचिका फिर से सुनवाई के लिए नहीं आई है।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत के १२ राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून 'राजनीति से प्रेरित' हैं। बयान में सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर भी प्रकाश डाला गया है कि उत्तर प्रदेश का हालिया संशोधन विधेयक, जो पीएमएलए और यूएपीए जैसे कानूनों के समान है, अनुच्छेद २५ के विरुद्ध हो सकता है।

जयपुर में LPG टैंकर में ब्लास्ट, अब तक ११ खोलकर भागने लगे. सड़क किनारे एक पाइप फैक्ट्री भी बनी हुई थी जिसमें आग लग गई. जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है वहां से महज १०० मीटर की दूरी पर क्रूड ऑइल की पाइप लाइन गुजर रही थी.डॉक्टर्स की मानें तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में ३२ झुलसे हुए लोगों को भर्ती किया गया था. डॉक्टर ने बताया कि ५ लोग हॉस्पिटल में मृत लाए गए थे. वहीं ५ लोगों ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है. ३२ में से १५ मरीज ऐसे हैं जो कि ५० प्रतिशत से ज्यादा झुलस चुके हैं. एक मरीज ने जयपुरिया हॉस्पिटल में दम तोड़ा है. हादसे में अभी तक कुल ११ लोगों की मौत हो चुकी है. जयपुर हादसे में उदयपुर की लेकसिटी ट्रेवल्स की बस भी चपेट में आई है. बस में ३४ सवारियां सवार थीं जिनमें से अभी तक २१ का पता चल पाया है अभी भी १३ लोगों की सूचना नहीं मिली है. यह बस रात ९ बजे उदयपुर से रवाना हुई थी.

परभणी हिंसा और सरपंच हत्याकांड मामले में भी की जाएगी. वहीं, मुख्यमंत्री ने देशमुख और सूर्यवंशी के परिजनों को १०-१० रुपए की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है.सीएम फडणवीस ने बीड के पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस की ओर से चूक हुई. सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत के मामले में भी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं. परभणी में संविधान की प्रतिकृति के अपमान के मामले पर हिंसा होने के बाद सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनकी हिरासत में मौत हो गई थी.परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर १० दिसंबर की शाम को बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान की प्रतिकृति पर लगा कांच तोड़े जाने के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसने हिंसक रूप ले लिया था. फडणवीस ने कहा, 'परभणी हिंसा की न्यायिक जांच कराकर सभी संदेह दूर किए जाएंगे. आंबेडकर किसी जाति तक सीमित नहीं हैं. वह सभी के हैं.'सरपंच संतोष देशमुख के अपहरण और हत्या से जुड़े मामले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बीते दिन बीड जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के पूर्व तहसील प्रमुख विष्णु चाटे को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया. जहां से उन्हें २७ दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. इससे पहले गिरफ्तार किए गए लोगों में जयराम चाटे, महेश केदार और प्रतीक घुले शामिल हैं. वहीं, पुलिस तीन अन्य लोगों की

निजी कार्य के लिए हो रहा है पुलिस बैरिकेड का उपयोग

रामदासपेठ थाना के तार फैल परिसर में आसानी से देखे जा सकते हैं बैरिकेड

क्या पुलिस प्रशासन करेंगा कार्रवाई..?

अकोला- (चांद रज़वी)

अकोला के रामदासपेठ पुलिस थाना अंतर्गत तार फाइल परिसर में पुलिस प्रशासन द्वारा त्यौहार उत्सव तथा विभिन्न अहम कार्यो के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बैरिकेड यह तारफाइल नायगांव मुख्य मार्ग पर निजी कार्य के लिए उपयोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं इन बैरिकेडों के कारण आधा रास्ता भी रोक लिया गया है जिसके चलते नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन कि यह लापरवाही नागरिकों के लिए सर दर्द बनी हुई है। नागरिकों का कहना यह भी है कि, रामदासपेठ पुलिस थाना के कर्मचारी परिसर में पेट्रोलिंग के लिए आते भी है किंतु उन्हें भी यह बैरिकेड दिखाई नहीं देते हैं।

आपको बता दे की तार फाइल के मुख्य मार्ग पर दो बैरिकेड आपको दिखाई देंगे जो आधा रास्ता रोक कर खड़े हुए दिखाई देते हैं। जिसमें पहला बैरिकेड यह विजयनगर सरकारी अस्पताल के पास लगाया गया है तो दूसरा दादा साहब मेश्राम शाला के समीप लगाया गया है। इस प्रकार सरकारी संपत्ति का नागरिक खुलेआम निजी उपयोग करके सीधे पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगा यह यहां पर सवाल उपस्थित होता है। हालांकि देखा गया है कि लोग सरकारी संपत्तियों से दूर रहना ही मुनासिब समझते हैं किंतु यहां पर खुले आम सरकारी संपत्तियों का उपयोग होना यह गंभीर है। नागरिकों की मांग है कि उक्त बैरिकेडों को वहां से हटाया जाए और आवागमन में होने वाली परेशानी को दूर किया जाए।

आयटक कामगार कर्मचारी संगठन का जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन

देश के गृहमंत्री अमित शाह से इस्तिफे की मांग

अकोला-

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आयटक कामगार कर्मचारी संघटना जिला शाखा अकोला द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय अकोला के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था जिसमें संघटना के पदाधिकारी तथा महिला पदाधिकारी सदस्यों की बड़ी संख्या में उपस्थिती देखने को मिली इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग की के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ बाबासाहेब अंबेडकर के संदर्भ में संसद में किए गए अपमान कारक वक्तव्य का हम निषेध करते है। उसी तरह महाराष्ट्र राज्य के परभणी शहर में संविधान की प्रतिमा के साथ हुई और अवहेलना और पुलिस की क्रूरता व कांबींग मुहिम में निर्दोष युवाओ पर कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी मार्फत देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्हें ज्ञापन सोपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि १९ एवं २० दिसंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन की ओर से राज्य में प्रदर्शन आयोजित किए गए है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संसद में किए गए वक्तव्य यह गंभीर है संविधान निर्माता के संबंध में एवं संविधान के संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा नियंत्रण रहने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भाजपा सरकार के मन में कितना द्वेष है यह एक बार फिर सामने आया है जिसके चलते गृहमंत्री अमित शाह ने माफी मांगनी चाहिए एवं गृह मंत्री पद का राजीनामा देना चाहिए इसके लिए महामहिम राष्ट्रपती द्वारा तत्काल हस्तक्षेप करें ऐसा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं अखिल भारतीय दलित अधिकार आंदोलन ने किया है। उसी तरह परभणी में हुई घटना की तफसीलवार जांच करने के लिए न्यायिक आयोग की स्थापना की जाए पुलिस की कार्रवाई में मृतक सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार को ५० लाख की मदद की जाए इस प्रकार की मांग भी दौरान रखी गई।

अकोला डेपो की शिवशाही बसे हुई भंगार

एसटी महामंडल की बसे कही भी हो जाती है बंद, यात्रियों को होती है परेशानी

अकोला-

अकोला डेपो की अधिकांश बसे भंगार हो गई है। किंतू इस भंगार बसो मे अब शिवशाही जैसी ऐसी बसो का भी समावेश होने का दिखाई दे रहा है। गुरूवार की शाम एक बस का ब्रेक फेल होने के कारण वह चालक सतर्कता से एक पेट्रोल पंप की दिवार से जा टकराई थी उसे २४ घंटो भी बिते नही थे की शुक्रवार की सुबह ८ बजे के समीप फिर एक बस अकोट फैल आपाताप चौक पर खराब हो गई जिसके कारण बस मे सवार यात्रियों को परेशानीयों का सामना करना पडा। लगातार बसो के बिच रास्ते खराब होने से यात्रियों को परेशानीयों सामना करना पडता है तथा दुसरी बस का इंतेजार करना पडता है। जिसके चलते उक्त बसों की जगह पर नई बसो को लाया जाए इसप्रकार की मांग यात्रियों द्वारा की जा रही है क्योंकी भंगार बसो मे यात्रियों को अपनी जान जोखीम मे डालकर यात्रा करनी पड रही है किंतू एसटी प्रशासन कुंभकरण की नींद सोया हुआ है।

अंक तथा विज्ञापन के लिए संपर्क
7620469536,9923333517

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबासाहेब आंबेडकर को लेकर दिए गए संसद में बयान का विरोध

सामाजिक कार्यकर्ता शेख कमरुद्दीन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन

अकोला-

संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ बाबासाहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए अपने बयान को लेकर पूरे भारत भर में उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसके चलते अकोला में भी गृह मंत्री का विरोध प्रदर्शन किया गया। अकोला के खैर मोहम्मद प्लाट मदीना चौक परिसर में सामाजिक कार्यकर्ता शेख कमरुद्दीन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा देने की मांग की गई। शेख कमरुद्दीन द्वारा अपने विचार रखते हुए इस दौरान कहा गया कि देश के गृहमंत्री द्वारा इस प्रकार के देश के संविधान निर्माता डॉ बाबासाहेब के प्रति इस प्रकारकी भाषा का उपयोग करना उन्हें शोभा नहीं देता है उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए यही हमारी मांग है। इस विरोध प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ता इमरान खान, अमजद हुसैन हाजी साहब, रशीद खान, सत्तार भाई चाय वाले स्टेट ब्रोकर, शेख आबिद फ्रूट वाले, कयूम भाई किराना दुकान वाले, इलियास ठेकेदार, लियाकत साहेब, अल्ताफ साहेब, सज्जू साहेब आदि की प्रमुखता से उपस्थिति थी।

विहिप विदर्भ प्रांत की प्रयागराज के महाकुंभ मेले में प्रतिदिन रहेगी महाप्रसाद सेवा

पत्रकार परिषद मे दी जानकारी जानकारी

अकोलाड-

मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगनेवाले महाकुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद विदर्भ क्षेत्र द्वारा प्रतिदिन महाप्रसाद की सेवा की जाएगी यह जानकारी विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र मंत्री गोविंद शेंडे ने दी. इसमें नागरिकों से सहयोग करने का आह्वान किया. गुरुवार को आदर्श गोसेवा प्रकल्प हॉल में विहिप की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस सेवा उपक्रम की जानकारी दी. इस समय विदर्भ प्रांत मंत्री प्रशांत चितरे उपस्थित थे. विहिप विदर्भ प्रांत की ओरसे प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु-संतों को १३ जनवरी से २७ फरवरी तक हर दिन भोजन वितरित किया जाएगा. यह सेवा हर दिन सुबह १० बजे से रात १० बजे तक चलेगी. प्रतिदिन करीब १५ हजार श्रद्धालु इस महाप्रसाद सेवा का लाभ उठाएंगे. इस महाप्रसाद सेवा में कुंभ मेले में आनेवाले साधु-संतों को आसन पर बैठाकर भोजन परोसा जाएगा. अनुमान है कि, इस सेवा में करीब १५ हजार श्रद्धालु प्रतिदिन भोजन करेंगे. १२ साल बाद आनेवाले महाकुंभ मेले में ३५ करोड़ श्रद्धालु शामिल होंगे, जिसमें साधुओं की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद द्वारा की जाएगी. साधुओं के लिए ठहरने की और वहीं पर लंगर सेवा भी संचालित की जाएगी. इससे पहले श्री कुंभ मेले के दौरान भी श्रद्धालुओं ने कुंभ मेले में हिस्सा लिया था. अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद, विदर्भ प्रांत द्वारा एक माह तक महाप्रसाद सेवा का आयोजन किया गया था. इस सेवा से लगभग २० लाख श्रद्धालुओं को लाभ मिला. इसी तर्ज पर प्रयागराज में भी महाप्रसाद सेवा उपलब्ध कराई जाएगी.

महाकुंभ हर १२ साल में आता है और इस पावन अवसर का हिंदू धर्म में एक अलग और असाधारण महत्व है. इसलिए इस अवसर पर दान का महत्व है. इसी के तहत शेंडे ने विश्व हिंदू परिषद को इस भव्य उपक्रम मे अनाज और अन्य खाद्य सामग्री का सहयोग करने की अपील की है. इस अवसर पर प्रांत सेवा प्रमुख राम लोखंडे, धर्माचार्य संपर्क प्रमुख सुरेश परसावार, प्रांत न्यास प्रमुख गणेश कालकर, बजरंग दल प्रांत सहसंयोजक सूरज भगेवार, संजय दुधे, हरिओम पांडे, नीलेश पाठक, संदीप निकम, प्रेम आमकर आदी उपस्थित थे.

मनपा उपायुक्त गीता ठाकरे ने स्वच्छता विभाग की समीक्षा की

अकोला-

स्वच्छ भारत अभियान के तहत - स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५, मनपा आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. सुनील लहने के आदेशानुसार. १९ दिसंबर २०२४ को नगर निगम उपायुक्त गीता ठाकरे ने अकोला नगर निगम के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मुख्य सभागृह में स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस बैठक में अकोला नगर निगम क्षेत्र में दैनिक स्वच्छता कार्य में और अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से प्रत्येक स्वच्छता निरीक्षक को अपने-अपने क्षेत्र में स्वच्छता कार्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे. इस पर विशेष ध्यान देने के लिए शहर की मुख्य सड़कों को पूरी तरह से साफ करने, हर शनिवार को सफाई करने और सड़क से धूल उठाने, साथ ही माननीय आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कचरा नहीं जलाने, इसके बाद एकत्र किए गए कचरे को उठाने की बात कही। सफ़ाई और कूड़ेदान के बाहर के क्षेत्र में या अन्यत्र भी। गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और उन्हें कूड़ा-कचरा कूड़ेदान में फेंकने के लिए प्रोत्साहित करना, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई करना, धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों, मैदानों, स्कूल परिसरों के खुले क्षेत्रों को सप्ताह में एक दिन साफ करने की योजना बनाना सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। एकल उपयोग कैरीबैग उपयोग, बिक्री, प्रतिबंधित नायलॉन, चाइनीज और सिंथेटिक कपड़ों के भंडारण और रख-रखाव के साथ-साथ बिक्री और उपयोग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

अकोला नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को अपने घरों और परिसर से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र करना चाहिए और इसे मोहल्ले और अन्यत्र डंप करने के बजाय, केवल नगर पालिका के कचरा बेल गाड़ियों में ही फेंकना चाहिए और पूरी तरह से बंद करके एकल उपयोग प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग जिसे सरकार के साथ-साथ नायलॉन, चीनी द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया है वहीं उपायुक्त गीता ठाकरे ने मनपा प्रशासन अपील की है कि सिंथेटिक चायनीज मांजे के इस्तेमाल से बचते हुए पतंग महोत्सव मनाकर मनपा प्रशासन को सहयोग करें.